

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

क्रमांक - 41/2024
अनवान :-

1. भूपसिंह पुत्र राजाराम जाति मेघवाल निवासी खचवाना तहसील भादरा।

- प्रार्थी

वनाम

1. मांगेराम पुत्र झिण्डूराम जाति मेघवाल निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।

-अप्रार्थी



प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

श्री संदीप गोदारा प्रार्थी
श्री श्रवण सहारण अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि रोही मौजा चक 1 एनटीआर के खाता सं० 38/51 के मु० न० 50 के किला न० 12 ता 14, 17 ता 20 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 21/1 की 0.228 है०, किला न० 21/2 की 0.025 है०, किला न० 22/1 की 0.228 है०, किला न० 22/2 की 0.025 है०, किला न० 23/1 की 0.228 है०, किला न० 23/2 की 0.025 है०, किला न० 24/1 की 0.228 है०, किला न० 24/2 की 0.025 है०, किला न० 25/1 की 0.215 है०, किला न० 25/2 की 0.038 है०, कुल 3.2890 है० जिसमें नहरी 3.1510 है०, गै० मु० रास्ता 0.138 है० में वादी भूपसिंह के नाम 590/3289 हिस्सा, पप्पूराम के नाम 84/3289 हिस्सा, प्रताप के नाम 3048/16445 हिस्सा, रामीदेवी के नाम 146/253 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम के नाम 537/16445 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी एवं दावा में अप्रार्थी सं० 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका मौखिक भाई बंटवारा होने के बाद अपने अपने हिस्सा अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे थे। परन्तु प्रताप ने बिना खाता व लगान अलग करवाये ही पूर्व में भी अप्रार्थी सं० 1 मांगेराम को भूमि विक्रय कर दी थी। एवं वर्तमान में भी अप्रार्थी बिना खाता व लगान अलग करवाये भूमि की अच्छी किस्म को बैचान करने पर उतारू है। अतः प्रार्थी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबन्द करवा पाने के कानूनी अधिकारी है कि वे उक्त को खुर्द-बुर्द ना करें एवं मौका व रिकार्ड की यथार्थिति बनाये रखे।।



प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं० 1 को जरिये सूचना तलब किया गया। अप्रार्थी सं० 1 तामिल उपरान्त जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र

पेश किया।

भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहरा अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि रोही एनटीआर के खाता सं० 38/51 के मु० न० 50 के किला न० 12 ता 14, प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 21/1 की 0.228 है०, किला न० 21/2 की 0.025 है०, किला न० 22/1 की 0.228 है०, किला न० 22/2 की 0.025 है०, किला न० 23/1 की 0.228 है०, किला न० 23/2 की 0.025 है०, किला न० 24/1 की 0.228 है०, किला न० 24/2 की 0.025 है०, किला न० 25/1 की 0.215 है०, किला न० 25/2 की 0.038 है०, कुल 3.2890 है० जिरामें नहरी 3.1510 है०, गै० मु० रास्ता 0.138 है० में वादी भूपसिंह के नाम 590/3289 हिस्सा, पप्पूराम के नाम 84/3289 हिस्सा, प्रताप के नाम 3048/16445 हिस्सा, रागीदेवी के नाम 146/253 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम के नाम 537/16445 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी एवं दावा में अप्रार्थी सं० 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका मौखिक भाई बंटवारा होने के बाद अपने अपने हिस्सा अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे थे। परन्तु प्रताप ने बिना खाता व लगान अलग करवाये ही पूर्व में भी अप्रार्थी सं० 1 मांगेराम को भूमि विक्रय कर दी थी। एवं वर्तमान में भी अप्रार्थी बिना खाता व लगान अलग करवाये भूमि की अच्छी किस्म को बेचान करने पर उत्तारू है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि के रिकार्ड व मौका की यथारिथति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अप्रार्थी सं० 1 किसी भी प्रकार का अजनबी व्यक्ति नहीं है। खचवाना, भरवाना व सरदारगढिया सारे गांव एक दूसरी से मिलते जुलते गांव है व एक दूसरे गांव की सीमा मिलती है। अस्थाई निषेधाज्ञा दरख्वास्त पेश करने से पूर्व सायल भूपसिंह ने न्यायालय में खाता विभाजन हेतु अर्जीदावा पेश किया हुआ था जिसमें न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी जारी जाकर विभाजन प्रस्ताव भी पेश किया जा चुका है, उक्त भूमि में से प्रताप द्वारा अपने हक हिस्सा में से 0.1074 हिस्सा भूमि का बैयनामा मिन मांगेराम के नाम से करवा दिया। जिराका नामान्तरण भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। प्रार्थी भूपसिंह जानबुझकर अप्रार्थी सं० 1 मांगेराम को खरीदशुदा भूमि को अपने उपयोग उपभोग में नहीं लेने देना चाहता व प्रार्थी भूपसिंह ने अप्रार्थी मांगेराम द्वारा खरीदशुदा भूमि पर काश्त की गई ग्वार की फसल को अन्य भाई-भतीजों के साथ मिलकर पक्की हुई फसल को ट्रैक्टर से निकालकर ले गया, उस पर खडे हरे पेड काटकर ले गया अब जबरदस्ती अप्रार्थी की खरीदशुदा भूमि में सरसों की बिजाई कर दी है। उक्त भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथारिथति बाबत अस्थाई की आड में प्रार्थी खुद अप्रार्थी को परेशान कर रहा है। एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज प्रावधानों कि सहखातेदार द्वारा किसी भी अन्य सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लिया जाना कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सब्यय खारीज किया जावे।

उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली क ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त कारण है तथा शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी है। उक्त भूमि के विभाजन का मूल वाद न्यायालय हाजा में जैरकार है। प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी भी वाद भूमि का सहखातेदार है। प्रार्थी के भाई प्रताप द्वारा अप्रार्थी सं० 1 मांगेराम को उक्त भूमि में से अपने घरेलू जरूरतों के लिए कुछ हिस्सा की भूमि का बेचान किया गया था व उक्त भूमि का नामान्तरण भी अप्रार्थी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार उक्त वादभूमि में प्रार्थी के साथ अप्रार्थी सं० 1 को भी उक्त वादभूमि के उपयोग उपभोग का उतना ही अधिकार है जितना प्रार्थी का है क्योंकि संयुक्त मुश्तर्का की भूमि में सह खातेदारों का उपयोग उपभोग करने सभी का बराबर का हक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित है।

2 सुविधा का संतुलन:- अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। उक्त वाद भूमि संयुक्त मुश्तर्का की खातेदारी दर्ज है संयुक्त मुश्तर्का की खातेदारी भूमि में सह खातेदारों को भूमि के उपयोग उपभोग में बराबर का हक होता है इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा से यदि अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है तो अपनी कृषि भूमि के नियमित उपयोग-उपभोग में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अतः सुविधा का संतुलन बिन्दू भी अप्रार्थी के पक्ष में एवं प्रार्थी के विरुद्ध साबित है।

3. अपूर्णाय क्षति:- उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन बिन्दू भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चूंकि उक्त विवादित रकबे पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के कारण अप्रार्थी को खातेदारी के उपयोग-उपभोग व अन्य विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त विवादित कृषि भूमि में प्रताप ने अपने हक हिस्से की वाद भूमि को घरेलू जरूरतों के हिसाब से बँट किया है यदि सम्पूर्ण वाद भूमि पर स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो अप्रार्थी सं० 1 भी अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगा यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश दिया जाता है तो अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के नियमित उपयोग उपभोग से वंचित किया जायेगा जिससे अप्रार्थी को अपूर्णाय क्षति होगी।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णाय क्षति बखूबी साबित होने एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट साबित नहीं होने के कारण खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक18.12.25.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिरीन)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला, हनुमानगढ़